†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तान के राष्ट्रपति १ सितम्बर, १९५९ को सवेरे ११ बजे के तुरन्त बाद पालम हवाई अड्डे पर उतरे। प्रधान मंत्री ने उनका स्वागत किया तथा वह लगभग डेढ़ घंटा पालम पर रुके। इसमें से अधिकांश समय में राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री ने अकेले ही विभिन्न मामलों पर बातचीत की। बातचीत की समाप्ति से कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त तथा भारत के राष्ट्रमंडलीय सचिव को भी बातचीत में हिस्सा लेने के लिये बुला लिया गया था। इस बैठक की समाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य दिया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की बातचीत अनौपचारिक तथा मित्रतापूर्ण थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की कि दोनों देशों के आपसी संबंध अच्छे पड़ौसियों के से होने चाहियें तथा उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको मित्रता-पूर्वक सुलझाया नहीं जा सकता है। प्रधान मंत्री उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत थे। किसी भी विशेष विषय पर विस्तारपूर्वक बातचीत नहीं की गई। दोनों देशों की कुछ समस्याओं का सरकारी तौर पर उल्लेख किया गया और राष्ट्रपति ने बताया कि यदि दोनों देशों के आपसी संबंध मित्रतापूर्ण हो जायें और दोनों के दिलों से भय और आशंकायें दूर हो जायें तो दोनों देशों का शस्त्रास्त्रों पर व्यय कम हो सकता है और इस धन को आर्थिक विकास में लगाया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने उनकी इस बात से सहमति प्रकट की और कहा कि भारत का मुख्य उद्देश्य अपना सामाजिक और आर्थिक विकास करना है और विकास के अपने इस कार्यक्रम को भारत ने अपनी पंच वर्षीय योजनाओं में सम्मिलित कर रखा है। दोनों का विचार था कि प्रत्येक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो जिससे दोनों देशों की जनता का कल्याण हो सके। ऐसा करने के लिये निश्चित रूप से बहुत पैसा चाहिये और प्रतिरक्षा व्यय में बचत करके धन उपलब्ध किया जाये तो निश्चय ही यह बहुत अच्छा होगा।

नहरी पानी विवाद पर विश्व बैंक के प्रतिनिधियों की सहायता से जो बातचीत हो रही है उसके बारे में भी कुछ जिक्र किया गया तथा आशा व्यक्त की गई कि यह विवाद सन्तोषजनक रुप में निबट जायेगा।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री दोनों ने पूर्वी सीमा पर होने वाली घटनाओं और झगड़ों के चलते चले आने के संबंध में चिन्ता व्यक्त की। इन घटनाओं का, जिनमें प्रायः गोलियां भी चलाई जाती हैं, कतई कोई औचित्य नहीं है और न ही इससे किसी को लाभ हो सकता है। इससे सिर्फ स्थानीय जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तथा दोनों देशों का वातावरण दूषित होता है। दोनों इस बात से सहमत थे कि इन झगड़ों को समाप्त किया जाना चाहिये और इनको समाप्त करने के बारे में कोई प्रक्रिया बनाई जानी चाहिये। हाल में ही मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के समाप्त हो जाने के बाद जो वक्तव्य दिया गया था वह एक अच्छा वक्तव्य था। अच्छे सिद्धांत या अच्छी नीति बनाने में तो कोई कठिनाई नहीं होती है, परन्तु उनको लागू करने में ही कठिनाई होती है। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि इस काम के लिये एक उच्चस्तरीय सम्मेलन किया जाना चहिये। यह सम्मेलन मंत्रियों के स्तर पर होना चाहिये जिसमें वरिष्ठ सेना कमांडर, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा प्रतिनिधि सम्मिलित हों। जहां संभव हो झगड़ों के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और सीमा निर्धारण का काम शीघ्रता से किया जाना चाहिये। एक ऐसी प्रक्रिया भी बनाई जानी चाहिये जिससे पूर्वी क्षेत्र की सीमा पर होने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वाली किसी घटना के बारे में शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके। प्रधान मंत्री इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत थे और यह निर्णय किया गया कि ऐसा सम्मेलन बुलाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

लन्दन में इंडिया आफिस लाइब्रेरी का उल्लेख किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि इस लाइब्रेरी के बारे में भारत तथा पाकिस्तान दोनों को मिलकर कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

पुराने दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास के भवनों के संबंध में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये, जिन पर अविभाजित भारत सरकार के राजस्व से धन व्यय किया जाता था और जो अब भी ब्रिटेन की सरकार के कब्जे में है।

†**श्री अजराज सिंह** : (फिरोजाबाद) : क्या प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान जाते हुये अथवा वहां से लौटते हुये पाकिस्तान में जाने का निर्णय किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे निर्णय करने का प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि मैंने इस पर विचार ही नहीं किया है। मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु ऐसा करना कठिन है। वह मेरे रास्ते में नहीं है और न ही मेरे कार्यक्रम में यह ठीक बैठता है।

†**श्री सूपकार** : क्या नेहरू-नून समझौते पर कोई बात हुई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ढाका में कहा है कि इस बैठक में काश्मीर का प्रश्न भी उठाया गया था। क्या वास्तव में इसका उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से राष्ट्रपति अय्यूब खां ने काश्मीर के बारे में इतना ही कहा था कि हमारी सारी समस्यायें जिनमें काश्मीर की समस्या भी है, शांति से सुलझाई जा सकती हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत था।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारयण सिंह)** : श्रीमान् आप की अनुमति से मैं आगामी सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) २७ मई, १९५९ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, जीवन बीमा निगम जांच के बारे में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा भारत सरकार के संकल्प पर चर्चा।

(२) गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के ३०, जुलाई, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ की अवधि के लिये प्रथम प्रतिवेदन पर चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में